



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—पर्याप्ति-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राचीकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 526]

नई विल्सो, मंगलवार, दिसम्बर 29, 1992/पौष 8, 1914

No. 526] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 1992/PAUSA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विन मंत्रालय
(गजस्व विभाग)
चिरेन कर तथा कर अनुसंधान
अधिकारी
नई विल्सो, 29 दिसम्बर, 1992

आयकर

रा. का. नि. 950(श) —यत, दो देशों के बायु पारवहन उद्यमों के क्रियाकलापों की आय पर करों की पारस्पर्यक छूट के द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के लिये भारत सरकार तथा मऊदी अरब किंगडम के बीच सम्पन्न भलग्न करार, उक्त करार के अनुच्छेद 6 के द्वारा यथा निर्दिष्ट उन पत्रों के आदान-प्रदान के जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उचित प्रक्रिया पूरी की गई थी, माठ विन बाद 25 मितम्बर 1912 को लाग् हा गया है।

यह, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 तथा कंपनी (लाभ) अतिकरक प्रधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा यह निर्देश देनी है कि उक्त करार के सभी उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी बनाया जाये।

अनुवन्ध

भारत गणराज्य तथा मऊदी अरब किंगडम के बीच, दोनों देशों के बायु परिवहन उद्यमों के कार्यकलापों में प्राप्त आय पर करों की पारस्परिक छूट द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के लिये करार।

भारत गणराज्य तथा मऊदी अरब किंगडम अंतर्राष्ट्रीय यातायान में बायु परिवहन के सञ्चालन में उद्यमों तथा उनके कर्मचारियों को प्राप्त आय पर आयद करों की पारस्परिक छूट द्वारा दोहरे कराधान के परिहार के

लिये एक करार सम्पन्न करने की छवि में तीव्र विवेद
अनुमार महसूत हुए हैं।—

प्रत्यक्षित—1

परिभासा:

1. इस करार में जब तक कि विषयगत पाठ में
अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदा-
कारी राज्य" पदों में, विषयगत पाठ की
अपेक्षा के अनुमार भारत अथवा सऊदी अरब
किंगडम अभिप्रेत हैं,

(ख) "कर" शब्द में, विषयगत पाठ की अपेक्षा
के अनुमार "सऊदी कर" अथवा "भारतीय
कर" अभिप्रेत है;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य का वायु परिवहन
उद्यम" पद में—

(i) सऊदी अरब के मामले में सऊदी अरब एवं
लाइन कार्पोरेशन अथवा उनराधिकारी;

(ii) भारत के मामले में एवं चिंडिया अथवा
उसका उनराधिकारी; अभिप्रेत हैं;

(घ) "वायु परिवहन का परिचालन" पद में एक
संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा
हवाई जहाज द्वारा प्राप्तियाँ, अस्माबाब, पशुओं
माल-अथवा डाक को नाने—ले जाने का
कारोबार करना, अभिप्रेत है, जिसमें टिकटो
की विक्री तथा परिवहन के प्रयोजनार्थ
प्रयुक्त ममस्त दस्तावेज भी शामिल हैं,

(इ) "अन्तर्राष्ट्रीय यानायात" पद में—एक संविदा-
कारी राज्य के किसी वायु परिवहन से
मम्बद्ध उद्यम द्वारा उसके स्वामिन्व के, पट्टे
पर लिये गये अथवा अवकीत तथा संचालित
वायुयान द्वारा किया गया कोई परिवहन अभिप्रेत
है जिसके उद्यम स्थिति के जब ऐसा परिवहन
केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के
बीच ही किया जाता है;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" पद में—

(i) भारत के मामले में, वित्त मन्त्रालय, राजस्व
विभाग में केन्द्रीय सम्पादक;

(ii) सऊदी अरब के मामले में, त्रिन मंत्रालय तथा
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था,
अभिप्रेत है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद
में—ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर
उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत, उसके
अधिकार, निवास, प्रबंध-व्यवस्था का स्थान

अथवा समस्त स्वस्त के किसी अन्य तानाशाह
के कानून उस राज्य में कर लगाया जा सकता
है,

(ज) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कोई निगम,
कोई कंपनी अथवा व्यक्तियों का कोई अन्य
निकाय शामिल है,

(झ) "अन्य अदायगिया" पद में सामाजिक सुरक्षा
बीमा, बुडापे की वापिकी अथवा पैण्ड,
बीमारी अथवा चिकित्सा बीमा, बेतोजगार
बीमा अथवा संविदाकारी राज्य के कानून
द्वारा कर्मचारियों के बेतन तथा भत्तों पर
आयद आय के अनुपात में की गई नई अन्य
दायागिया अभिप्रेत है।

2. संविदाकारी राज्यों में किसी एक राज्य द्वारा
इस करार के उपबन्धों का प्रयोग करने में प्रयुक्त किसा
शब्द का, जिसमें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है,
जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित रहे हों,
वही अर्थ होगा जो ऐसे करों में संवर्तित सभी राज्य
के कानूनों के अन्तर्गत है, जो इस करार के लिए है।

प्रत्यक्षित—2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य के ओर से
आयद पर लगाये गये करों पर लागू होगा, भले हो उनको
आयद करने का तरीका कुछ भी हो।

2. कुल आय पर, अथवा आय के तत्वों पर लगाये
गये सभी करों को आय पर कर के रूप में समझा
जायेगा, जिसमें तब समाति के अन्तरण में प्राप्त होने
वाले अधिलाभों पर कर तथा उसमा द्वारा प्रदत्त मज़दूरी
अथवा बेनेंटों को कुल रकम पर कर भी शामिल है।

3. मौजूदा कर, जिन पर यह करार विशेष रूप
में लागू होगा, निम्नानुसार है—

(क) भारत के मामले में—

(i) आयकर जिसमें उम पर लगाया गया काइ
अधिभार भी शामिल है;

(ii) अस्तिकर

(जिन्हें एतद्पश्चात् "भारतीय कर" के रूप में
उल्लिखित किया गया है);

(ख) सऊदी अरब किंगडम के मामले में :

आयकर

(जिसे एतद्पश्चात् "सऊदी कर" के रूप में उल्लिखित
किया गया है)।

4. यह करार किसी ममस्त अथवा पर्याप्त रूप ग
उसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा जिन्हें नाम में

इम अनुच्छेद के पैग्राफ ३ में उल्लिखित करों के अर्थात्, अथवा उनके बदले में लगाया जाना हो। सविदाकारी राज्यों के सबसे प्राधिकारी पूर्क-हस्ते को उनके मबद्धिन करावान कानूनों में किये गये किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे म अधिसूचित करेगे।

अनुच्छेद—३

आय का कराधान

१ एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये गये वायु परिवहन में प्राप्त आय तथा लाभों को दूसरे सविदाकारी राज्य म दर से छूट प्राप्त होगी।

२ पैग्राफ १ के उद्धवध एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा किसी पल अथवा किसी समयकृत वायु परिवहन सचालन में उसकी भाष्टेदारी ये प्राप्त आय तथा लाभों पर भी लाग होगे।

३ इम अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ एक सविदाकारी राज्य के किसी वायु परिवहन उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायु परिवहन के सचालन से प्राप्त वायुमें निम्नलिखित में प्राप्त आय भी शामिल हैं

(क) दूसरे सविदाकारी राज्य ने उद्यम को वायायात अथवा भूमि उपकरण के किनाये अथवा पटटे में प्राप्त आय,

(ख) दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम को प्रशिक्षण याजनाश्री, प्रब्रह्म-व्यवस्था तथा दी गई अन्य सेवाओं में प्राप्त आय।

४ पैग्राफ १ के प्रयोजनार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयात के सचालन में प्राप्त वायु निवाया गया तथा अथवा उसी समान की आय को वायुयात के गंचालन में प्राप्त हुई आय के स्थ में समस्ता जायेगा।

अनुच्छेद—४

वैयक्तिक सेवाओं के लिये पारिश्रमिक

दोनों सविदाकारी राज्य, उनमें से किसी एक सविदाकारी राज्य के वायु परिवहन उद्यम के किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा परिवधियों पर, जहाँ-कहीं वे प्राप्त किये गये हो, आयद अथवा आयद किये जाने वाले सभी करों तथा अन्य अदायगियों का छूट देने का वायदा बहुत है, वर्णने कि वह दूसरे सविदाकारी राज्य का एक नागरिक हो।

अनुच्छेद—५

पारम्परिक करार कार्यविधि तथा विवादों का निपटान

१ इम करार में संगोधन किये जाने के प्रयोजनार्थ दोनों में किसी एक सविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी समय परामर्श करने के लिये अनुरोध किया जा

सकेगा। ऐसा परामर्श, उसके लिये किसी ऐसे अनुग्रह के प्राप्त होने की तारीख से ९० दिन के भीतर प्राप्त रहेगा।

२ सविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी उस करार के अर्थनिष्पत्ति में अथवा उसको नाम अन्ने में पदा होने वाली किसी प्रकार की कठिनाइयों अथवा नंदेहों का समाधान परस्पर सहमति के द्वारा करेगे।

अनुच्छेद—६

प्रबन्धन

१ उस करार को प्रत्येक सविदाकारी राज्य म प्रवृत्त कानूनों के अनुसार अनुमोदित प्रथमा अनुसंगतिन किया जायेगा। यह करार इस आशय के कागजान के आवान-प्रदान करने के बाद, जिसमें यह प्रभागित किया जायेगा कि प्रत्येक सविदाकारी राज्य में समूचित कार्यविधि को पूर्ण किया गया, साठ दिन के बाद प्रवृत्त होगा। कागजान का आशान-प्रदान गजनगिक माध्यमों के द्वारा किया जायेगा।

२ इस करार के उपर्यन्त जनवरी, १९७० के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् प्राप्त ही गई आय के सवध में प्रभावी होगे।

अनुच्छेद—७

समाप्त

यह करार अनिश्चित वाल तक प्रवृत्त रहेगा तक उसे दोनों में भी किसी भी सविदाकारी राज्य द्वारा किसी भी कैलेंडर दर्प की समाप्ति से कम ग अम छ माह पूर्व समाप्त का नोटिस इकार समान दिन जा सकेगा, उस स्थिति में, यह करार उस कैलेंडर दर्प के प्रति में, जिसमें समाप्त का नोटिस दिया जाना है, निप्रभावी हो जायेगा।

जिसके मात्र में विधिवत् प्राधिकृत अधीक्ष्माकार्या न उस करार पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उस पर प्राप्ती मोहर लगाई है।

नई दिल्ली में एक हजार नी सी छकानवे के नवम्बर माह के चौदहवें दिन अर्थात् ४वें जुमादा I, १४१२ को हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में हा मूल प्रतियों में निष्पत्ति किया गया जिसके भर्ती पाठ समान स्थ में प्राप्तिक है। तीन पाठ में परस्पर मिलता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की श्रोत्र में

डा. मनमोहन मिह,

वित्त मंत्री

मउदी अरब किंगडम की सरकार की ओर से

अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अल-

जमील, उद्योग तथा विद्या मंत्री

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Revenue)
 FOREIGN TAX & TAX RESEARCH
 NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1992

INCOME-TAX

G.S.R. 950(E).—Whereas the annexed Agreement between the Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia for avoidance of double taxation by reciprocal exemption of taxes on income on the activities of air transport enterprises of the two countries has entered into force on the 25th September, 1992 after sixty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting State, as required by Article 6 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT
 BETWEEN

THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
 BY RECIPROCAL EXEMPTION OF TAXES
 ON INCOME ON THE ACTIVITIES OF
 AIR TRANSPORT ENTERPRISES OF THE
 TWO COUNTRIES

The Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia desiring to conclude an Agreement for Avoidance of Double Taxation by Reciprocal Exemption of Taxes levied on income of enterprises and their employees from operation of air transport in international traffic have agreed as follows :—

Article 1

DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :—

- (a) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean India or the Kingdom of Saudi Arabia, as the context requires;
- (b) the term “tax” means “Saudi tax” or “Indian tax” as the context requires;
- (c) the term “air tr...”

- (i) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia, the Saudi Arabian Airlines Corporation or its successor;
- (ii) in the case of India, Air India or its successor;
- (d) the term “operation of air transport” means the business of transportation by air of passengers, baggage, livestock, goods or mail conducted by an enterprise of a Contracting State including sale of tickets and similar documents used for the purpose of transport;
- (e) the term “international traffic” means any transport by aircraft owned, leased or chartered and operated by an air transport enterprise of a Contracting State, except when such transport is made solely between places in the other Contracting State;
- (f) the term “Competent authority” means
 - (i) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia the Ministry of Finance & National Economy;
 - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue;
- (g) the term “resident of a Contracting State” means any person, who under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature;
- (h) the term “person” includes an individual, a corporation, a company or any other body of persons;
- (i) the term “other payments” means social security insurance, old age annuity or pension, sickness or medical insurance, unemployment insurance or any other payments measured by income levied on the salaries and allowances of the employees by the law of the Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term used but not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular;

- (a) in the case of the Kingdom of Saudi Arabia the income-tax, (hereinafter referred to as "Saudi Tax");
- (b) in the case of India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon;
 - (ii) the sur-tax (hereinafter referred to as "Indian Tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes as are subsequently imposed in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

TAXATION OF INCOME

1. Income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from the operation of air transport in international traffic shall be exempted from tax in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income and profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State from its participation in a pool or a joint air transport operation.

3. For the purposes of this Article, profits derived by an air transport enterprise of a Contracting State, from the operation of air transport in international traffic also include income derived from :

- (a) the rental or lease of aircraft or ground equipment to the enterprise of the other contracting State;
- (b) training schemes, management and other services rendered to the enterprise of the other Contracting State.

4. For the purposes of paragraph 1, interest or similar earnings on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of aircraft.

Article 4

REMUNERATION FOR PERSONAL SERVICES

The two Contracting States undertake to extend exemption of all taxes and other payments levied or to be levied on salaries, wages, allowances and perquisites, wherever received, by an employee belonging to the air transport enterprise of either Contracting State provided that he is a citizen of the other Contracting State.

Article 5

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE AND SETTLEMENT DISPUTES

1. Consultation may be requested at any time by either Contracting State for the purpose of amendment to this Agreement. Such consultation shall begin within 90 days from the date of receipt of any such request.

2. The competent authorities of the Contracting States shall resolve by mutual agreement any difficulties or doubts regarding the interpretation or application of this Agreement.

Article 6

ENTER INTO FORCE

1. This Agreement shall be approved or ratified in accordance with the laws in force in each of the Contracting States. It shall enter into force sixty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting States. The exchange of letters shall be through diplomatic channels.

2. The provisions of this Agreement shall have effect in respect of income derived on or after the 1st day of January 1970.

Article 7

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but may be terminated by either Contracting State by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year, in which case, this Agreement shall cease to have effect from the end of the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF THE undersigned do¹ authorized thereto, have signed this Agreement, have affixed thereto their seal

Done at New Delhi this 14th day of November, 1991, corresponding to 8th Jumada I, 1412, in two originals, in the Hindi, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Dr. Manmohan Singh,
Minister of Finance

Abdul Aziz Abdullah Al-Zamil
Minister of Industry and
Electricity

[No. 9152 F. No. 501/6/74-FTD]
T. S. KRISHNA MURTHY, Jt. Secy.

